भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1191

उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

डिजिटल अधिगम, अनुसंधान और रचनात्मक तकनीकी पहलों का विस्तार

1191. **श्री सतीश कुमार गौतमः**
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री भर्तृहरि महताबः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
डॉ. के. सुधाकरः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री शंकर लालवानीः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
सुश्री बाँसुरी स्वराजः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री नव चरण माझीः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री राजीव प्रताप रूडीः
श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये के नए बजट का उपयोग करने के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश बनाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, साथ ही देश के सरकारी और माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नियत किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) 200 करोड़ रुपये के आवंटन से सहायता प्राप्त पीएम रिसर्च चेयर योजना के अंतर्गत शोधार्थी, स्वीकृत की गई रिसर्च चेयर, चयनित संस्थान और लाभार्थियों के चयन के राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या मापदंड हैं;
(ग) देश में कितने माध्यमिक विद्यालयों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई के साथ मिलकर एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई हैं, साथ ही, इन विद्यालयों के चयन के मापदंडों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने डिजिटल अवसंरचना के कार्य को तीव्रता से करने और सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार (मेरिट) योजना के अंतर्गत वित्तपोषण के नियमों में संशोधन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं और जारी की गई निधि सहित छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत आने वाले तकनीकी संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा गुजरात के अरावली और साबरकांठा जिलों जैसे ग्रामीण, सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों और राज्य के अन्य आकांक्षी जिलों, विशेषकर कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के छात्रों और शिक्षकों तक डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(च) क्या सरकार का महाराष्ट्र में, विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, एआई-सक्षम डिजिटल अधिगम सुविधाएं, एवीजीसी प्रयोगशाला और अनुसंधान अवसंरचना बनाने का विचार है; और
(छ) आंध्र प्रदेश में डिजिटल अवसंरचना और बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए सहायता पाने वाले तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संस्थानों का ब्यौरा क्या है, साथ ही राज्य में ऐसी पहलों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा मंत्रालय डिजिटल शिक्षा और अवसंरचना के संवर्धन का कार्य ₹100 करोड़ के अलग से किए गए स्वतंत्र आवंटन के बजाय अपनी प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत करता है। आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) प्रयोगशालाओं तथा स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना हेतु केंद्र द्वारा प्रबंधित वित्त पोषण और कार्यक्रमात्मक क्रियान्वयन "समग्र शिक्षा – कार्यान्वयन हेतु रूपरेखा" में निर्धारित संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। (https://www.dsel-education.gov.in/static/uploads/2025/09/bab5af8d0e4cb47c3727b6450d0217a7.pdf).

(ख): प्रधान मंत्री रिसर्च चेयर (पीएमआरसी) योजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 13 विषयगत क्षेत्रों में 3 श्रेणियों अर्थात् युवा अनुसंधान अध्येता (पीएचडी के बाद 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक), वरिष्ठ अध्येता (पीएचडी के बाद 5 से 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक) और रिसर्च चेयर (पीएचडी के बाद 10 वर्ष से अधिक का अनुभव) में भारत के बाहर का अनुभव रखने वाले भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और पेशेवरों को सहायता प्रदान करना है। योजना का ब्यौरा (पात्रता मानदंड और पात्र संस्थानों की सूची सहित) पीएमआरसी पोर्टल https://pmrc.education.gov.in/about पर उपलब्ध है।

(ग): भारत सरकार ने विद्यार्थियों को एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स में उद्योग-प्रासंगिक कौशलों से युक्त करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (आईआईसीटी), मुंबई के सहयोग से 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की घोषणा की।

(घ): सरकार ने 275 तकनीकी संस्थानों में गुणवत्ता, समता और अभिशासन में सुधार हेतु 4,200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एमईआरआईटीई (तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार) योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना का हिस्सा हैं।

(ङ): शिक्षा मंत्रालय गुजरात के अरावली और साबरकांठा जिलों सहित देश भर के ग्रामीण, दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के संवर्धन हेतु समग्र शिक्षा के तहत पीएम ई-विद्या और दीक्षा जैसी आईसीटी और डिजिटल पहलों को कार्यान्वित करता है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकता के अनुसार आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में दिनांक 17 मई, 2020 को पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो देश भर में शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। पीएम ईविद्या के प्रमुख घटक डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं और इसमें 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं, जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। पीएम ईविद्या 200 डीटीएच टीवी चैनल पहल के तहत, गुजरात राज्य (जीजे पीएम ईविद्या 78-82) को पांच समर्पित चैनल आवंटित किए गए हैं।

भारत सरकार ने बजट 2025 में गुजरात के 1,416 सरकारी ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों सहित दूरदराज के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल द्वारा 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की पेशेवर दक्षताओं को बढ़ाने के लिए, निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल) नामक व्यापक स्तर का एक समग्र कार्यक्रम शुरू किया। यह गुजरात सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म पर प्रत्यक्ष, ऑनलाइन तथा मिश्रित प्रशिक्षण मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

(च): महाराष्ट्र राज्य में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत, योजना के विभिन्न घटकों के तहत 1431.31 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि के साथ कुल 144 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसमें बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालय सुदृढ़ीकरण अनुदान (जीएसयू), कॉलेज सुदृढ़ीकरण अनुदान (जीएससी), नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) और लैंगिक समावेशन व समता पहल (जीआईईआई) के घटकों को शामिल करते हुए योजना अर्थात पीएम उषा के तीसरे चरण के तहत 814.24 करोड़ की राशि की 61 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम-उषा के तहत 25 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाओं सहित जलगांव जिले में 52 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(छ): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केंद्रीय सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) सहित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू की हैं। सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने हेतु रूसा के पूर्व चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियों सहित, जून 2023 में 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण शुरू किया है। इस योजना को पीएम-उषा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2028 तक और वर्तमान में जारी रूसा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने (अर्थात 30 सितंबर, 2026) तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना में विभिन्न घटकों अर्थात् बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालय सुदृढ़ीकरण अनुदान (जीएसयू), कॉलेज सुदृढ़ीकरण अनुदान (जीएससी), नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) और लैंगिक समावेशन व समता पहल (जीआईईआई) के तहत सहायता के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है।

पीएम-उषा के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में 378.74 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित राशि के लिए कुल 33 इकाइयों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें एमईआरयू घटक के तहत श्री पद्मावती महिला विश्व विद्यालय, तिरुपति को 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी शामिल है।

एमईआरयू घटक के तहत, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से उच्चतर स्तर की पहुंच, समता और उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा समग्र और बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए (i) राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) का कार्यान्वयन तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रणाली का कार्यान्वयन; (ii) अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को अपनाना; आदि जैसी विभिन्न अनिवार्य गतिविधियां करने की अपेक्षा की जाती है।

*****